International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume V, Issue IV, December 2018 Available online at: www.ijaur.com

भारत में वित्तीय समावेशन की उपादेयता

डॉ0 रोशनलाल पाण्डेय[1] एवं आशुतोष द्विवेदी [2]
1. वाणिज्य शा0 शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महा0 मऊगंज रीवा (म0प्र0)
2. शोधार्थी वाणिज्य अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0)

सारांश– किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यदि बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नही बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था की औपचारिकता माध्यम में शामिल कर सकें। भारत जैसे विकासशील देश जहॉ बहुसंख्यक जनसंख्या गरीब है वहॉ लोंगो के आर्थिक स्तर को ऊॅचा उठाने तथा सामाजिक और आर्थिक न्याया की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई वित्तीय समावेशन की योजनाऍ लोगों को आर्थिक अधिकार प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हुई हैं सरकार वित्तीय समावेशन प्रणाली में प्रत्येक परिवार के लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबंध है ऐसा करने का एकमात्र उददेश्य देश के विकास में प्राप्त विधिक लाभों को जन–जन तक पहुॅचाना और साथ ही जनता के द्वारा जुटाई गई निधियों को औपचारिक चैनल में शामिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक संभल मिल सके ताकि विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

मुख्य शब्द – आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन एवं अर्थव्यवस्था ।

प्रस्तावना –
किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढांचा होता है। यदि बुनियादी ढांचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नही बनाया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किए जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था की औपचारिकता माध्यम में शामिल कर सकें।

वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति भी आार्थिक विकास के लाभ से संबद्ध किया जा सके कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधार से बंचित ना रहे इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया था ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गरीब आदमी को बचत करने के साथ–साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पृष्ठभूमिः–
वर्ष 1980 और 1990 के दशक में शुरू किए गए ढांचागत समायोजन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप हुए वित्तीय सुधारों का लाभ अनेक विकासशील देशो को मिला।

यदि भारत के संबंध में बात करें तों बीसवीं शताव्दी के आरंभ में केवल एक बीमा कंपनी (जो जीवन बीमा एवं कुछ साधारण बीमा योजना का संचालन करती थी) और एक स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत थे। परंतु अब यह देश बदल गया वर्तमान में देश में 20 से अधिक बैंक अनेक बीमा कंपनियां तथा स्टॉक एक्सचेजों के साथ साथ कई प्रकार के विधि संस्थान कार्यरत है। वस्तुतः इसका मूल कारण आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हुआ देश का व्यक्ति समावेशी विकास है।

वित्तीय समावेशन के विषय में यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि इसका कार्य क्षेत्र केवल बैकिंग सेवाओं तक ही सीमित नही है बल्कि यह बीमा इक्विटी उत्पादों और पेंशन उत्पादों आादि विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं के संबंध में भी समान रूप से लागू होता है।

वित्तीय समावेशन का अर्थ बैंकिग सेवाओं से वंचित किसी भी क्षेत्र में स्थित बैंक शाखा में केवल एक बैंक खाता खोलना मात्र कतई नही है। वित्तीय समावेशन के प्रभाव से उत्पन्न चुनौतियां वस्तुतः किसी व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का अभाव होना समाज एवं व्यक्ति दोनो के लिए हानिकारक होता हैं जहां तक व्यक्ति क्या संबंध है वित्तीय समावेशन के अभाव में बैको की सुविधा से वंचित लोग मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिग क्षेत्र से जुडने के लिए बाध्य हो जाती है इन क्षेत्रों में व्याज की दरें भी अधिक होती है और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है। जहॉ तक सवाल है वित्तीय समावेशन के सामाजिक लोगों का तो आपको बताते चले कि वित्तीय समावेशन के परिणाम स्वरूप ना केवल उपलब्ध बचत राशि में वृद्वि होती है बल्कि वित्तीय मध्यस्ता की दक्षता में भी बृद्धि होती है इतना ही नही नित नए व्यवसायिक अवसरों को प्राप्त करने की सुविधा भी प्राप्त होती हैं इस परिस्थिति में सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व सुलभ बैंकिग प्रणाली के परिणाम स्वरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बैंकिग परिवेश की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आार्थिक विविधीकरण में योगदान प्राप्त हुआ है।

वित्तीय समावेशन के लाभः–
आम आदमी को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शाामिल किए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ भी प्राप्त होते है जहॉ एक ओर इसमें समाज के कमजोर तबके के लोगों को उनकी जरूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के ईधन की बचत करने विभिन्न वित्तिय उत्पादों जैसे बैकिंग सेवाओं बीमा और पेंशन उत्पादों आादि में भाग लेकर देश के आर्थिक

कियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है वही दूसरी ओर इस से देश को पूंजी निर्माण की दर में बृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ–साथ आार्थिक कियाकलापों को भी संवर्धन प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त वे लोग जो वित्तीय दृष्टि से विकास की मुख्यधारा में शामिल नही हुए है अपनी बचत तथा निवेश को भूमि भावन अथवा गहने आादि जैसी अनुत्पादक आस्तियों में लगााते है जबकि वित्तीय दृष्टि से अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शाामिल लोग इन सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर पाते है फिर चाहे वह संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो अथवा असंगठित क्षेत्र में रहते हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र से सरकार का सरकारी सब्सिडी तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतराल एवं हेराफेरी पर रेाक लगााने में भी मदद मिलती है क्योकि इससे सरकार उत्पादों पर सब्सिडी देने की वजह सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।

वित्तीय समावेशन में सरकार द्वारा उठाये गये कदमः–

देश के प्रत्येक व्यक्ति के वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए–

(1):– प्रधानमंत्री जन–धन योजना–

- बैंकिंग सेवाओं की पहुॅच में वृद्धि करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खााता हो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमत्रीं जनधन येाजना नामक एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की घोषणा की गई।
- अगस्त 2017 के मध्य तक इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 29.48 करेाड बैंक खाते खोले गए जो अपने आप में एक बहुत बडी उपलब्धि है।
- ध्यातव्य कि इन खातों में से तकरीबन 17.61 करोड खाते ग्रामीण और शहरीं क्षेत्रों और 30111087 करेाडपति शहरी क्षेत्र में खोले गए।

जनधन योजना के तहत खाता खोलने पर मिलने वाले लाभः–

- ग्राहक को एक रूपये डेबिट कार्ड जारी किया जाता है इसमें 1 लाख रूपयें का बीमा कवर होता है।
- खाते को 6 महीने तक संतोषजनक रूप से संचालित करने पर ग्राहक को रू 5000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- ग्राहक को एक विशेष समय तक खाता खोले रहने के लिए रू 30000 का जीवन बीमा भी दिया गया है।

(2):– बीमा और पेंशन स्कीमः–

- सभी नागरिकों और विशेष गरीब एवं सुविधा रहित लोंगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई।
- पूर्व की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी एम एस बी आई) में 18 से 70 वर्ष की आयु समूह को कवर किया गया था जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी लोगो को कवर किया गया है जिनके पास बैंक खाते मौजूद है।
- यह योजना केवल रू 12 वार्षिक के बहिनी प्रीमियम पर 2 लााख रूपये का जोकिंग खबर प्रदान करती है।

(3):– अटल पेंशन योजना–

- इस योजना की वर्ष 2015 में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी खाताधारकों के लिए शुरू किया गया था।
- इस स्कीम के अंतर्गत अभिदाता का मासिक पेंशन की गारंटी प्रदान की जाती है।
- इसके तहत केंन्द्र सरकार द्वारा भी कुल अंशदान के 50 प्रतिशत का योगदान किया जाता है बशर्ते कि यह रू1000 प्रति वर्ष से अधिक ना हो।
- वे सभी अभिदाता जिन्होने 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक भी.पी.बी.वाई. में आवेदन किया है उन्हें 9 प्रतिशत का सुनिश्चित गारंटी रिटर्न प्रदान किया जाएगा।

(4):– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

- इस योजना को गैर कॉरपोरेट्स लघु व्यापार क्षेत्र को औपचारिक विधि सुविधाएं प्रदान करने के लिए अप्रैल 2015 में शुरू किया गया ।
- इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की गैर वित्त पोषित क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं बैंक वित्तपोषण सुनिश्चित करना है।
- देश में वित्तीय समावेशन का बढावा देने के लिए और भी बहुत सी योजनाओं को शुरू किया गया जिसमें जीवन सुरक्षा बंधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सामान्य क्रेडिट कार्ड और भीम ऐप जैसी योजनाऍं शामिल है।

(5):– स्टैंड–अप इंडिया–

- इस योजना को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यमरें के लिए 10 लाख रू से 1 करोड रू तक के बैंक ऋण तथा पारिवारिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

- इस योजना के अंतर्गत अगस्त 2017 के मध्य तक 38,477 धारकों को लगभग 8,277 करोड रूपयें के ऋण वितरित किए जा चुके है।
- देश में वित्तीय समावेशन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ए.टी.एम. स्थापित करने की सलाह दी गई है जिसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2016 तक लगभग माइक्रों ए.टी. एम. स्थापित किए जा चुके है।

(6):– वेंचर केपिटल स्कीम–

- सरकार द्वारा अनुसूवित जाति/जन्मजात वर्ग के लोगो को रोजगार मांगने की बजाए रोजगार देने की दिशा में प्रयत्न करते हुए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना में योग्यजनों को पहले 50 लाख रूपए से 15 करोड रूपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता था जिसकी सीमा बाद में घटाकर 20 लाख रूपये से 15 करोड रूपए तक निर्धारित कर दी गई ।
- जाति/जनजाति के लोगो को रोजगार आश्रित न रहकर रेाजगार उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है।

(7):– अन्य पहल–

- ए.टी.एम. और वाइट लेवल ए.टी.एम. की नीतियों का उदारीकरण किया गया है।
- ए.टी.एम. के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए आरबीआई द्वारा गैर बैंकिग संस्थाओं की ए.टी.एम. शुरू करने की अनुमति भी दी गई।
- आरबीआई के अनुरोध पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों तक जनता की पहुचं सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता और शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय जागरूकता केन्द्र शुरू किए गये।
- आधार और बैंक खातो की सहायता से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सफल बनाना एक बहुत बडी उपलब्धि है।

निष्कर्ष:–

निष्कर्ष के रूप में कह सकते है कि भारत जैसे विकासशील देश जहॉ बहुसंख्यक जनसंख्या गरीब है वहॉ लोंगो के आर्थिक स्तर को ऊॅचा उठाने तथा सामाजिक और आर्थिक न्याया की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई वित्तीय समावेशन की योजनाऍ लोगों को आर्थिक अधिकार प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हुई हैं सरकार वित्तीय समावेशन प्रणाली में प्रत्येक परिवार के लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबंध है ऐसा करने का एकमात्र उददेश्य देश के विकास में प्राप्त विधिक लाभों को जन–जन तक पहुॅचाना और साथ ही जनता के द्वारा जुटाई गई निधियों को औपचारिक चैनल में शामिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक संभल मिल सके ताकि विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

संदर्भ:–

- कुरूक्षेत्र पत्रिका (2016–2018)
- प्रतियोगिता दर्पण (2017–2018)
- योजना पत्रिका (2016–2018)
- प्रतियोगिता दर्पण
- क्रॉनिकल पत्रिका (2017–2018)
- दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं
- इंटरनेट
- अन्य